corporate entity for the time being. However, it feels that IBP needs a strong strategic partner for continued supply of products and also providing marketing back up and necessary financial support. Accordingly, it endorses the views of the Disinvestment Commission that Government of India should disinvest 33.58% in favour of a strategic partner. After careful study and consideration at various strategic alliance options, based on various success factors, the Committee feels that BPC is a strong candidate in comparison to other oil companies. Therefore, Government of India should disinvest its shareholdings in IBP in excess of 26% in favour of BPC as permissible under the SEBI take over guidelines. If these guidelines stand in the way of one shot of acquisition of this block of shareholding by BPC, this may have to be done in phases or a portion of the shareholding now held by financial institutions may have to be transferred to BPC.

(f) IBP should be assured of the required products from Mathura and/or Panipat in the North and MRL and CRL in the South throught appropriate marketing tie-ups for a period of at least five years after the end of APM period in order to maintain its supplies.

(g) Government of India should constitute a petroleum regulatory body in lieu of OCC, who should regulate the supply of products besides handing critical issues during the transition period of deregulation.

(h) All the existing pipelines excluding strategic pipelines owned by IOC should be transferred to an independent company such as the Petronet India Limited so that all the marketing companies get fair and equitable access to these pipelines for movement of products.

(i) After implementation of the recommendation, the Committee has identified that there will be three market players, e.g., IOC, HPC and BPC-IBP. It feels that at a later date, the possibility of a combination of HPC, BPC-IBP, CRL, MRL AND NRL should be explored through an umbrella of a holding company. This new entity will be equal in size to IOC and would not only provide good competition but could also emerge as a global player in competition with the international oil majors.

*

गुजरात में कच्चे तेल का उत्पादन

2727. **श्री गोविन्दराम मिरी:**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार तेल और प्राकृतिक गैस निगम तथा अन्य निजी उपक्रमों द्वारा पिछले पांच वर्ष में गुजरात तथा अन्य राज्यों में अपने अपने क्षेत्रों में कितने मीट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या गुजरात तथा अन्य राज्यों को उक्त अवधि के दौरान कच्चे तेल पर रायल्टी का भुगतान किया गया;

(ग) क्या रायल्टी की दर में कोई असमानता है; और

(घ) उपर्युक्त कच्चे तेल की मात्रा में यदि कोई विसंगति है, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) गुजरात और अन्य राज्यों में ओ एन जी सी/ओ आई एल और निजी/संयुक्त-उद्यम कंपनियों द्वारा किए गए कच्चे तेल के उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए)

(ख) से (घ) गुजरात और अन्य राज्य सरकारों को बिना किसकी भेदभाव के "लेखागत" दर पर कच्चे तेल पर रायल्टी का भुगतान किया गया। पिछले पांच वर्षों के लिए रायल्टी की अंतिम दरें नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा विधिवत रूप से लेखापरीक्षित ओ एन जी सी और ओ आई एल के उत्पादन आंकड़ों की लागत के आधार पर अधिसूचित की जाएगी। अंतिम रायल्टी दरों की अधिसूचना के बाद समायोजन किया जाएगा।

विवरण

कच्चे तेल का कम्पनी-वार और राज्य-वार उत्पादन

(मिलियन टन)

कम्पनी/राज्य		1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99* (अप्रैल-फरवरी)
क.	ओ एन जी सी	29.356	31.635	28.685	28.250	24.429
	गुजरात	6.279	6.362	6.159	5.950	5.334
	असम	2.195	2.190	1.964	2.047	1.887
	आन्ध्र प्रदेश	0.271	0.044	0.052	0.066	0.078
	तमिल नाडु	0.385	0.374	.329	0.324	0.335
	बम्बई हाई अपतट	20.226	22.665	20.181	19.863	16.795
ख.	ओ आई एल	2.883	2.882	2.870	3.094	3.008
	असम	2.849	2.854	2.834	3.069	2.974
	अरुणाचल प्रदेश	0.034	0.028	0.036	0.025	0.034
ग	निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियां	—	0.650	1.346	2.514	2.670
	गुजरात	—	0.023	0.025	0.028	0.028
	असम/अरूणाचल प्रदेश	—	0.003	0.014	0.015	0.039
	पूर्वी अपतट	—	0.157	0.811	1.960	1.606
	पश्चिमी अपतट	—	0.467	0.496	0.511	0.997
	कुल जोड़ (क+ख+ग)	32.239	35.167	32.901	33.858	30.107

पेट्रोलियम क्षेत्र का कार्य-निष्पादन

2728. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्र लाभ अर्जक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में पूंजी की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है तथा उत्पादन में तेजी लाई जा सकती है;

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में किए गए पूंजी निवेश का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार के आकलन के अनुसार उक्त वर्षों के दौरान कुल कितने अनुमानित पूंजी-निवेश की आवश्यकता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) देश का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्र नाममात्र का लाभ कमाने वाला क्षेत्र है क्योंकि दो राष्ट्रीय तेल कम्पनियां अर्थात ओ एन जी सी और ओ आई एल जो अधिकतर उत्पादन करती हैं, लगातार लाभ कमाती रही हैं। देश के पेट्रोलियम संसाधनों के मूल्य को अधिकतम करने और प्रचालनों को आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं। इसी के साथ साथ अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र की पूंजीगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए आंतरिक संसाधन जुटाने को अधिकतम करने पर बल दिया जाता